Azadi Ka Amrit Mahotsav

GURU DEEKSHAA IAS

सम्पूर्ण-संक्षिप्त-समर्थ

CURRENT AFFAIRS गुरु

UPSC/State PSC परीक्षा की तैयारी करने वाले हिंदी माध्यम के छात्रो के लिए

22nd September 2022

FOR DAILY FREE CURRENT AFFAIRS
Follow Our Youtube Channel

Guru Deekshaa Hindi

INDEX

DAILY CURRENT AFFAIRS NOTES

22nd September 2022

1. - डिजिटल उधार: 3

(i) के बारे में: 3

(ii) ऑनलाइन उधार बाजार का श्रृंगार क्या है? 3

(iii) भारत में डिजिटल लेंडिंग मार्केट कितना उन्नत है? 3

(iv) डिजिटल लेंडिंग की लोकप्रियता इतनी तेजी से क्यों बढ़ी है? 4

(v) डिजिटल ऋण देने के कौन से लाभ अधिक उल्लेखनीय हैं? 4

(vi) ऑनलाइन उधार के संबंध में क्या चिंताएं मौजूद हैं? 5

(vii) आरबीआई के नए नियम क्या हैं, और वे समस्याओं का समाधान कैसे करते हैं? 5

(viii) आगे बढ़ने का रास्ता: 6

(ix) निष्कर्ष: 7

2. - ढेलेदार त्वचा रोग: 8

(i) ढेलेदार त्वचा रोग क्या है? 8

(ii) रोकथाम और उपचार: 8

3. - ला नीना: 9

(i) के बारे में: 9

(ii) ला नीना के प्रभाव: 9

(iii) ला नीना के प्रभावों में शामिल हैं: 10

4. - ई - सिम प्रौद्योगिकी: 11

(i) के बारे में: 11

(ii) क्या फायदे मौजूद हैं? 11

(iii) क्या नकारात्मक पहलू मौजूद हैं?..... 11

संपादकीय विश्लेषण..... 13

1. ईडब्ल्यूएस आरक्षण:..... 13

(i) ईडब्ल्यूएस कोटा: ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:..... 13

(ii) ईडब्ल्यूएस कोटा की शुरुआत: 13

(iii) कोटा का क्या मतलब है:..... 13

(iv) अनुभाग का निर्धारण करते समय किन मानदंडों पर विचार किया जाता है?..... 14

(v) इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित में से किसी भी वस्तु के स्वामी होने से व्यक्ति EWS पूल से बाहर रह सकता है:..... 14

(vi) अदालत के मानकों के बारे में क्या चिंताएं हैं? 14

(vii) ईडब्ल्यूएस कोटा की वर्तमान स्थिति क्या है? 14

(viii) ईडब्ल्यूएस कोटा के साथ व्यावहारिक समस्याएं:..... 15

(ix) क्या भारत में आरक्षण की आवश्यकता है? 15

(x) आगे बढ़ते हुए: 16

(xi) निष्कर्ष:..... 16

2. जी 20: 17

(i) के बारे में: 17

(ii) G20 का गठन कैसे हुआ? 17

(iii) G20 की प्रक्रिया क्या है?..... 17

(iv) G20 में कौन शामिल है?..... 17

(v) G20 की संरचना और उद्देश्य क्या हैं? 17

(vi) G20 के लाभ और सफलताएँ क्या हैं? 18

(vii) G20 के सामने क्या चुनौतियाँ हैं?..... 19

(viii) भविष्य क्या ला सकता है?..... 19

1. - डिजिटल उधार:

GS III

विषय→अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दे

➢ **संदर्भ:**

- भारत के रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मंगलवार को अत्यधिक ब्याज दरों, अनैतिक संग्रह विधियों और डेटा गोपनीयता चिंताओं के बारे में कई शिकायतों का हवाला देते हुए डिजिटल ऋण देने के बारे में चिंता व्यक्त की। यह सुनिश्चित करने के लिए कि ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए उनकी सुरक्षा की गई थी, उन्होंने फिनटेक क्षेत्र के लिए शासन, कॉर्पोरेट आचरण, नियामक अनुपालन और जोखिम में कमी पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

के बारे में:

- डिजिटल तकनीक के परिणामस्वरूप ऋण क्षेत्र हाल ही में बदल गया है। बेहतर ग्राहक अनुभव, त्वरित प्रतिक्रिया समय और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और मशीन लर्निंग (एमएल) जैसी आधुनिक तकनीक के अनुप्रयोग की इच्छा के परिणामस्वरूप ऋण देने का परिदृश्य बदल गया है। लेकिन डिजिटल युग में मौजूदा उधार परिदृश्य के साथ कई समस्याएं हैं। इन चिंताओं को दूर करने के प्रयास में, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ऐसी गतिविधियों के लिए नियामक वातावरण को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किए गए दिशानिर्देश तैयार किए हैं। जनवरी 2021 में स्थापित "डिजिटल लेंडिंग, जिसमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप्स के माध्यम से ऋण शामिल है" (डब्ल्यूजीडीएल) पर कार्य समूह ने सिफारिशें प्रस्तुत कीं, जिसने सबसे वर्तमान नियमों के निर्माण को प्रभावित किया।

ऑनलाइन उधार बाजार का श्रृंगार क्या है?

- वेबसाइटों या मोबाइल एप्लिकेशन पर प्रौद्योगिकी द्वारा संभव किए गए उधार को "डिजिटल उधार" कहा जाता है। स्वचालित तकनीकों और एल्गोरिदम का उपयोग ग्राहक अधिग्रहण, क्रेडिट मूल्यांकन, निर्णय लेने, प्रमाणीकरण, संवितरण और वसूली के लिए किया जाता है। लागत कम करने के अलावा, यह तेजी से भुगतान की गारंटी भी देता है।
- चूंकि ऋण सेवा प्रदाता (एलएसपी) और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) ग्राहकों को ऋण (या ऋण की लाइनें) प्रदान करने के लिए मिलकर काम करती हैं, इसलिए पूर्व के मंच के कई पक्ष हैं।

भारत में डिजिटल लेंडिंग मार्केट कितना उन्नत है?

- डिजिटल लेंडिंग भारत में फिनटेक उद्योगों में से एक है जो सबसे तेजी से बढ़ रहा है। यह 2012 में 9 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2019 में लगभग 110 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है।
  इसके अलावा, यह अनुमान लगाया गया है कि डिजिटल वित्तपोषण के लिए बाजार 2023 तक लगभग 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आकार तक बढ़ जाएगा।
- इस उद्योग में मुख्य खिलाड़ी नव-बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय संगठन और फिनटेक स्टार्टअप (एनबीएफसी) हैं।
- इसके उपभोक्ताओं में, विशेष रूप से, बिना क्रेडिट इतिहास वाले छोटे उधारकर्ता शामिल हैं, जिन्हें पारंपरिक वित्तीय संस्थानों द्वारा सेवा नहीं दी जाती है।

अल्पकालिक ऋण, विशेष रूप से 30 दिनों से कम अवधि के ऋण, उनकी विशेषज्ञता का मुख्य क्षेत्र हैं।

- वाणिज्यिक बैंकों द्वारा भी वित्तीय मध्यस्थों की भूमिका पर तेजी से कब्जा किया जा रहा है। ये बैंक या तो एनबीएफसी के साथ स्वतंत्र रूप से काम करते हैं या डिजिटल उधार के माध्यम से तालमेल बनाने के लिए उनके साथ संयुक्त रूप से काम करते हैं।

डिजिटल लेंडिंग की लोकप्रियता इतनी तेजी से क्यों बढ़ी है?

- सबसे पहले, ब्लॉकचेन, क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अन्य तकनीकों के तेजी से विकास के साथ-साथ तेज और कम खर्चीली इंटरनेट कनेक्टिविटी ने फिनटेक स्टार्ट-अप के उदय में योगदान दिया है। इसके अतिरिक्त, उधार विकसित हुआ है और "डिजिटल हो गया है।"
- दूसरा, प्रधान मंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) कार्यक्रम के अगस्त 2015 के शुभारंभ के लिए धन्यवाद, अब उधारदाताओं के पास पिछले दस वर्षों में बैंकों द्वारा बनाए गए बड़े ग्राहक आधार के तालमेल तक पहुंच है।
- तीसरा, इस क्षेत्र के पास एक बड़ा अवसर है जो पर्याप्त निवेश को आकर्षित कर रहा है। पिछले सात वर्षों में डिजिटल ऋण देने वाले प्लेटफार्मों ने 19.6% चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर दिखाई है।
- चौथा, केपीएमजी के अनुसार, अर्थव्यवस्था और सेवाओं के तेजी से डिजिटलीकरण ने वित्तीय समावेशन और डिजिटल उधार में काफी सुधार किया है।

डिजिटल ऋण देने के कौन से लाभ अधिक उल्लेखनीय हैं?

- आसान ऋण वितरण: डिजिटल ऋण देने वाले प्लेटफार्मों ने उधारकर्ताओं के लिए भौगोलिक बाधाओं को दूर करके तुरंत ऋण के लिए आवेदन करना संभव बना दिया है। उनके पास सीधी डेटा प्रविष्टि, एक व्यक्तिगत उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस और त्वरित ऋण आवेदन प्रक्रियाएँ हैं।
- कम त्रुटियां: डिजिटल उधार का उपयोग करते समय मानवीय त्रुटि की संभावना कम होती है क्योंकि आवेदक की जानकारी प्राप्त करना आसान होता है। दस्तावेजों की डिजिटल स्कैनिंग का उपयोग उनकी प्रामाणिकता को जल्दी और सटीक रूप से सत्यापित करने के लिए किया जा सकता है।
- प्रभावशीलता बढ़ाता है एक डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म लागत में आधी कटौती करते हुए प्रभावशीलता बढ़ा सकता है। डिजिटल वित्तपोषण उधारदाताओं और उधारकर्ताओं के बीच संबंधों में सुधार करता है, अधिक धन और विकास उत्पन्न करता है, और समय बचाता है।
- बेहतर ग्राहक अनुभव डिजिटल उधार में त्वरित प्रतिक्रिया समय होता है और उधारकर्ताओं को ऋण निर्णय के लिए लंबा इंतजार करने से बचाता है। इसके अतिरिक्त, इसके परिणामस्वरूप, बैंक ऋणों के प्रबंधन में कम समय और धन खर्च करते हैं। बैंक अधिक ऋण और उत्पादों को संभाल सकते हैं और उधारकर्ताओं को एक बेहतर अनुभव दे सकते हैं यदि उनके पास त्वरित ऋण स्वीकृति और पैसा है।

ऑनलाइन उधार के संबंध में क्या चिंताएं मौजूद हैं?

- सबसे पहले, कई अन्य साथियों के साथ बाजार में अपनी स्थिति स्थापित करने के लिए, एलएसपी आमतौर पर उन उधारकर्ताओं को ऋण देकर खतरनाक ऋण संचालन में भाग लेते हैं जो उन्हें वापस भुगतान करने में असमर्थ हैं। सभी ग्राहकों के बीच इसे फैलाने और उच्च ब्याज दरों को लागू करने से जोखिम कम हो जाता है।
- प्रकटीकरण और खुलेपन के लिए नियामक आवश्यकताओं की अनुपस्थिति में एक भागीदार की परिचालन वैधता का आकलन करना मुश्किल था, जो हमें हमारे दूसरे बिंदु पर लाता है। जनवरी और फरवरी 2021 के बीच, भारतीय एंड्रॉइड उपयोगकर्ताओं के लिए 1,100 से अधिक ऋण ऐप उपलब्ध थे, जिनमें से 600 अवैध थे। उन्हें या तो आरबीआई के नियमन से छूट मिली हुई थी या उनके पास 1,000 करोड़ रुपये से कम की संपत्ति वाले एनबीएफसी भागीदार थे।
- मिससेलिंग, निजता का उल्लंघन, अनुचित व्यावसायिक व्यवहार, अत्यधिक ब्याज दरें लागू करना और अनैतिक वसूली तकनीक डिजिटल उधार के साथ कुछ अन्य समस्याएं हैं।

आरबीआई के नए नियम क्या हैं, और वे समस्याओं का समाधान कैसे करते हैं?

- आरबीआई ने डिजिटल उधारदाताओं को तीन श्रेणियों में विभाजित किया है: (1) वे जो इसके नियमन के अंतर्गत आते हैं और जिन्हें ऋण देने का व्यवसाय करने की अनुमति है; (2) वे जो अन्य वैधानिक या नियामक प्रावधानों के अंतर्गत आते हैं लेकिन आरबीआई के विनियमन के अधीन नहीं हैं; और (3) वे जो ऐसे किसी वैधानिक या नियामक प्रावधान के दायरे से बाहर उधार दे रहे हैं।
- प्रथम श्रेणी की संस्थाओं के लिए जिन पर आरबीआई का नियंत्रण है, कुछ नियम लागू होते हैं। आरबीआई ने सक्षम नियामक, नियंत्रण प्राधिकरण, या केंद्र सरकार से दूसरी और तीसरी श्रेणी के अंतर्गत आने वाले अधिक संगठनों के लिए सिफारिशें बनाने का अनुरोध किया है।
- नए नियमों का मूल सिद्धांत पारदर्शिता है।
- ऋण केवल विनियमित संस्थाओं द्वारा किए जा सकते हैं, जिन्हें या तो आरबीआई द्वारा शासित होना चाहिए या ऐसा करने के लिए कानूनी लाइसेंस होना चाहिए। उद्योग की पर्याप्त आउटसोर्सिंग को देखते हुए, यह नियामक मध्यस्थता से निपटने में भी मदद करेगा।
- आरबीआई ने अनिवार्य किया कि एलएसपी के नोडल पास-थ्रू खाते का उपयोग करने से बचने के लिए सभी ऋण संवितरण और पुनर्भुगतान सीधे उधारकर्ता और कंपनी के बैंक खातों के बीच किए जाएं।
- उधार लेने की लागत का खुलासा किया जाता है: वार्षिक प्रतिशत दर के रूप में दर्शाए गए डिजिटल ऋणों की कुल लागत, सभी शुल्क और लेवी के साथ, उधारदाताओं द्वारा एक समान तरीके से (एपीआर) उधारकर्ताओं को प्रकट करना होगा। वार्षिक प्रतिशत दर, जिसमें सभी शुल्क शामिल हैं, का उपयोग उधार लेने की लागत (एपीआर) को व्यक्त करने के लिए किया जाता है।

- अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले, उन्हें सभी डिजिटल ऋण उत्पादों के लिए एक मानक तरीके से उधारकर्ता को एक महत्वपूर्ण तथ्य विवरण (केएफएस) प्रदान करना होगा। इसके अलावा, इससे उधारकर्ताओं के लिए उद्योग में प्रतिद्वंद्वियों के प्रस्तावों के खिलाफ अपने प्रस्तावों का आकलन करना आसान हो जाएगा।
- क्रेडिट सीमा की स्वचालित वृद्धि: आरबीआई कहता है कि स्वचालित क्रेडिट सीमा में वृद्धि की अनुमति नहीं है जब तक कि उधारकर्ता लिखित रूप में और फाइल पर स्पष्ट रूप से सहमत न हो। इन विनियमित व्यवसायों को उन एलएसपी और डीएलए (डिजिटल लेंडिंग ऐप्स) की एक सूची प्रकाशित करनी चाहिए, जिनका उपयोग उन्होंने अपनी वेबसाइट पर किया है, साथ ही उन्हें दी गई जिम्मेदारियों के बारे में विवरण भी दिया है।
- डिजिटल ऋण देने के लिए एलएसपी के साथ साझेदारी करने से पहले उन्हें एक सख्त ड्यू डिलिजेंस प्रक्रिया से भी गुजरना होगा। उन्हें अन्य बातों के अलावा, इसके तकनीकी कौशल, डेटा गोपनीयता कानूनों और भंडारण तकनीकों को ध्यान में रखना चाहिए।
- एक विशेष समाधान संरचना के मानदंडों को पूरा करने के लिए, संस्थाओं को एक शिकायत निवारण अधिकारी बनाने की आवश्यकता होगी। यदि शिकायत प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर हल नहीं होती है, तो आरबीआई की एकीकृत लोकपाल योजना (आरबी-आईओएस) भी पारिस्थितिकी तंत्र के प्रभारी होंगे।
- डेटा संग्रह और साझा करना: ऐप्स द्वारा एकत्र की गई सभी जानकारी "ज़रूरत-आधारित" होनी चाहिए और इसमें उधारकर्ता की स्पष्ट, पूर्व सहमति होनी चाहिए। पहले दी गई अनुमति को रद्द करने का विकल्प उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध है। गोपनीयता नीति में नामांकन के दौरान एकत्र की जाने वाली जानकारी को रेखांकित करने की आवश्यकता है। आरबीआई का कहना है कि किसी भी व्यक्तिगत जानकारी को किसी तीसरे पक्ष के साथ साझा करने से पहले उपयोगकर्ता की मंजूरी आवश्यक है।
- प्रस्तावों में कहा गया है कि डीएलए के माध्यम से किए गए सभी उधार, इसकी प्रकृति या लंबाई की परवाह किए बिना, क्रेडिट सूचना फर्मों (सीआईसी) को बताए जाने चाहिए। इसके अतिरिक्त, सीआईसी को उधार देने के बॉय नाउ पे लेटर (बीएनपीएल) तरीके के बारे में सूचित किया जाना चाहिए।

आगे बढ़ने का रास्ता:

- सबसे पहले, आरबीआई के अनुसार, कार्य समूह की कुछ सिफारिशों, जैसे कि अनियमित उधार प्रथाओं को अवैध बनाने के लिए लिखित कानून, के लिए अतिरिक्त सरकारी इनपुट की आवश्यकता होती है। इसे सुधारने के लिए सरकार को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए।
- दूसरा, बिना बैंक खातों वाले लोगों का दूसरा सबसे बड़ा प्रतिशत अभी भी भारत में पाया जाता है। 190 मिलियन से अधिक वयस्क भारतीयों के पास किसी भी प्रकार का बैंक खाता नहीं है, जो एक महत्वपूर्ण अवसर पैदा करता है। जन धन योजना के लिए बैंकिंग संवाददाताओं को वित्तीय समावेशन में सुधार के लिए प्रोत्साहन मिलना चाहिए।

निष्कर्ष:

- इसकी मापनीयता को देखते हुए, डिजिटल ऋणदाता जल्द ही महत्व में पारंपरिक उधारदाताओं से आगे निकल सकते हैं, इस तथ्य के बावजूद कि इस समय बाजार में उनकी हिस्सेदारी कम हो सकती है। नई सीमाएं डिजिटल ऋणदाताओं द्वारा नियोजित परिचालन ढांचे को कैसे प्रभावित करेंगी यह अभी भी अज्ञात है। उधार देने वाले संगठनों या प्लेटफॉर्म ऑपरेटरों पर अनुचित बोझ के बिना, नियमों ने उपभोक्ताओं (उधारकर्ताओं) के हितों की रक्षा करने का एक अच्छा काम किया है। वित्तीय समावेशन के सरकार के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए डिजिटल ऋण देने के पारिस्थितिकी तंत्र में बहुत सारे वादे हैं। इसलिए पारिस्थितिकी तंत्र को उचित रूप से पोषित और समर्थित होना चाहिए।

- *स्रोत→हिन्दू*

GURU DEEKSHAA IAS

2. - ढेलेदार त्वचा रोग:

GS II

विषय→स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे

➢ **संदर्भ:**

- मुंबई पुलिस ने इस बीमारी को रोकने के प्रयास में मवेशियों के परिवहन पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसके परिणामस्वरूप शहर के चारों ओर ढेलेदार त्वचा फैलती है। इसके अनुसार, मवेशियों को उस स्थान से नहीं ले जाया जा सकता जहां उन्हें उठाया जा रहा है या बाजारों में ले जाया जा रहा है। यह आदेश 14 सितंबर को लागू हुआ और 13 अक्टूबर तक वैध है। महाराष्ट्र में 127 जानवरों की मौत हो चुकी है, जहां यह बीमारी अब 25 जिलों तक पहुंच गई है। वर्तमान में, संक्रामक वायरल वायरस से संक्रमित मवेशी 10 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पाए जाते हैं। पिछले सप्ताह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के अनुसार, केंद्र और राज्य इस बीमारी के प्रसार का प्रबंधन कर रहे हैं, जो डेयरी उद्योग के लिए एक चुनौती बन गया है।

ढेलेदार त्वचा रोग क्या है?

कारण:

- मवेशी या पानी की भैंस गांठदार त्वचा रोग वायरस से संक्रमित हो जाते हैं, जो एलएसडी (एलएसडीवी) का कारण बनता है।
- खाद्य और कृषि संगठन की रिपोर्ट है कि मृत्यु दर 10% से कम है। (एफएओ)।
- जाम्बिया ने 1929 में ढेलेदार त्वचा रोग की एक महामारी की सूचना दी। इसे पहले जहर या कीड़े के काटने की प्रतिक्रिया का परिणाम माना जाता था।

संचरण:

- जानवरों के बीच गांठदार त्वचा रोग फैलाने वाले प्राथमिक काटने वाले कीड़े (वेक्टर) मच्छर और काटने वाली मक्खियाँ हैं।
- बुखार, आंखों और नाक से तरल पदार्थ का प्रवाह, होठों से लार का बहना और शरीर में छाले इसके प्रमुख लक्षण हैं।
- जब किसी जानवर को चबाने या खाने में परेशानी होती है, तो वह खाना बंद कर देता है, जिससे दूध का उत्पादन कम हो जाता है।

रोकथाम और उपचार:

- भारतीय पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम कई बीमारियों के टीकाकरण की लागत को कवर करता है।
- ढेलेदार त्वचा की स्थिति के इलाज के लिए कोई विशिष्ट एंटीवायरल दवाएं उपलब्ध नहीं हैं। मवेशियों के लिए एकमात्र उपलब्ध उपचार सहायक देखभाल है। यह त्वचा के दोषों के इलाज के लिए बार-बार होने वाले त्वचा संक्रमण और निमोनिया के साथ-साथ घाव देखभाल स्प्रे को रोकने के लिए दवाओं का उपयोग कर सकता है।
- जानवरों को भूख कम करने से बचाने के लिए उन्हें दर्द निवारक दवाएं दी जा सकती हैं।

- ***स्रोत→हिन्दू***

3. - ला नीना:

GS I

विषय→भूगोल

➢ **संदर्भ:**

- भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर का वर्तमान ला निया चरण कम से कम एक और छह महीने तक टिकने का अनुमान है, जिससे यह रिकॉर्ड किए गए इतिहास में सबसे लंबी ला निया घटनाओं में से एक है। यह भी अभूतपूर्व है कि 1950 के बाद से इसे तीसरे वर्ष में बढ़ा दिया गया है। इसके आने वाले महीनों में वैश्विक मौसम की घटनाओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने का अनुमान है और यह विभिन्न स्थानों में बाढ़ और सूखे को बढ़ा सकता है।

के बारे में:

- द लिटिल गर्ल को स्पेनिश में ला नीना के नाम से जाना जाता है। इसे एल विएजो, अल नीनो विरोधी, और बस "एक ठंढा घटना" के रूप में भी जाना जाता है।
- ला नीना की घटनाओं के दौरान, ऐसे समय हो सकते हैं जब पूर्व-मध्य भूमध्यरेखीय प्रशांत क्षेत्र में समुद्र की सतह का तापमान औसत से नीचे हो।
- यह महत्वपूर्ण है कि समुद्र की सतह के तापमान में कम से कम पांच लगातार तीन महीने के मौसम के लिए 0.9 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक की कमी आई है।
- जब ला नीना प्रकरण होता है, तो पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में पानी का तापमान सामान्य से अधिक ठंडा हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप पूर्वी भूमध्यरेखीय प्रशांत क्षेत्र पर एक मजबूत उच्च दबाव होता है।

ला नीना के प्रभाव:

- उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर, कर्क और मकर रेखा के बीच प्रशांत महासागर का क्षेत्र, जो ला नीना का कारण बनता है, में औसत से अधिक ठंडा पानी बनता है।
- ला नीना पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में औसत से कम हवा के दबाव से अलग है। ये कम दबाव वाले क्षेत्र अधिक वर्षा लाते हैं।
- ला नीना की घटनाओं का एक और परिणाम वर्षा है जो उत्तरी ब्राजील और दक्षिण-पूर्वी अफ्रीका में औसत से अधिक है।
- हालांकि, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में विनाशकारी बाढ़ ला नीना की मजबूत घटनाओं से जुड़ी हैं।
- ला नीना की एक अन्य विशेषता मध्य और पूर्वी प्रशांत क्षेत्र पर औसत से अधिक दबाव है।
- फलस्वरूप उस क्षेत्र में कम बादल और बारिश होती है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका के खाड़ी तट, दक्षिणी दक्षिण अमेरिका के पम्पास क्षेत्र और उष्णकटिबंधीय दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर सामान्य से अधिक शुष्क स्थिति दर्ज की गई है।

ला नीना के प्रभावों में शामिल हैं:

- अल नीनो पूरे यूरोप में तूफान की आवृत्ति को कम कर देता है।
- ला नीना अक्सर उत्तरी यूरोप में हल्की सर्दियाँ और दक्षिणी/पश्चिमी यूरोप में ठंडी सर्दियाँ प्रदान करता है, जो भूमध्यसागरीय क्षेत्र (विशेषकर यूके) में बर्फ का कारण बनता है।
- इनमें से अधिकांश स्थितियां महाद्वीपीय उत्तरी अमेरिका में मौजूद हैं। अधिक व्यापक प्रभावों में से एक भूमध्यरेखीय क्षेत्र के साथ तेज हवाएं हैं, खासकर प्रशांत क्षेत्र में।
- मध्य अटलांटिक और कैरिबियन में अनुकूल तूफान की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है।
- कई अमेरिकी राज्यों में बवंडर गतिविधि में वृद्धि।
- ला नीना के कारण इक्वाडोर और पेरू दोनों ही सूखे का अनुभव करते हैं।
- पश्चिमी दक्षिण अमेरिका में मछली पकड़ने का व्यवसाय अक्सर इसका लाभ उठाता है।
- पश्चिमी प्रशांत: ला नीना पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में, विशेष रूप से चीन और महाद्वीपीय एशिया में भूस्खलन की संभावना को बढ़ाता है, जो इसके प्रभावों के लिए सबसे अधिक संवेदनशील क्षेत्र हैं।
- यह ऑस्ट्रेलिया में बाढ़ को भी काफी बढ़ा देता है।
- पश्चिमी प्रशांत, हिंद महासागर और सोमालियाई तट के साथ तापमान में वृद्धि हुई है।

- ***स्रोत→हिन्दू***

4. - ई - सिम प्रौद्योगिकी:

प्रीलिम्स विशिष्ट विषय

➢ **संदर्भ:**

- eSIM, जिसे आमतौर पर एक एम्बेडेड सिम कहा जाता है, वास्तव में एक नई तकनीकी प्रगति नहीं है। हालाँकि, यह Google पिक्सेल श्रृंखला, सैमसंग गैलेक्सी S और Z-श्रृंखला, और Apple iPhones, विशेष रूप से iPhone 14 जैसे फिटनेस-केंद्रित पहनने योग्य और स्मार्टफ़ोन के कारण तेजी से लोकप्रियता प्राप्त कर रहा है, जो केवल यूएस में eSIM का समर्थन करता है।

के बारे में:

- पहला eSIM 2012 में विकसित किया गया था।
- इस उदाहरण में एम्बेडेड सिम के समान भौतिक संरचना में एक मानक सिम कार्ड चिप अपरिवर्तनीय रूप से शामिल किया गया है।
- एक फोन के अंदर एक eSIM पाया जा सकता है और यह कई घटकों से बना होता है जो एक नियमित सिम कार्ड के समान होते हैं। इसके अतिरिक्त, वे एक ही कार्य करते हैं, एक विशिष्ट पहचान के रूप में कार्य करते हैं जो दूरसंचार ऑपरेटरों और अन्य उपयोगकर्ताओं को आपके व्यक्तिगत स्मार्टफोन का पता लगाने में सक्षम बनाता है जब वे आपको कॉल या टेक्स्ट करते हैं।
- लेकिन चूंकि मदरबोर्ड जुड़ा हुआ है, इसलिए रीप्रोग्रामिंग भी संभव है, जिससे उपयोगकर्ता बिना किसी भौतिक सिम कार्ड को बदले वाहकों को स्थानांतरित कर सकते हैं।

क्या फायदे मौजूद हैं?

सुरक्षा:

- एक eSIM सिम चोरी के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है क्योंकि किसी अन्य डिवाइस में निकालने और उपयोग करने के लिए कोई भौतिक घटक नहीं है।
- आपके बैंक या सोशल मीडिया खातों में लॉग इन करने के लिए चोरी होने के बाद एक हमलावर आपके फोन का उपयोग नहीं कर सकता है।
- फ़ोन खोलने की संख्या कम की जा रही है:
- आपके फोन के फ्रेम में कम एपर्चर हैं, जिससे धूल और अन्य अशुद्धियों के अंदर जाने की संभावना कम हो जाती है।
- यह अन्य उद्देश्यों के लिए कुछ आंतरिक फोन स्थान भी उपलब्ध कराता है।

क्या नकारात्मक पहलू मौजूद हैं?

आपातकाल के समय:

- यदि आपका फोन खराब हो जाता है, बैटरी खत्म हो जाती है, या बस गिर जाती है और उसकी स्क्रीन टूट जाती है, तो सभी संपर्क कट जाएंगे। जबकि ऐसा हो रहा है, मानक सिम कार्ड को क्षतिग्रस्त फोन से आसानी से निकाला जा सकता है और बैकअप डिवाइस या अन्य फोन में डाला जा सकता है।

eSIM समर्थन के बिना देशों में अनुपयोगी:

- eSIM फोन का उपयोग उस देश में नहीं किया जा सकता जहां दूरसंचार ऑपरेटर वर्तमान में प्रौद्योगिकी को स्वीकार नहीं करते हैं।
- यदि आपका फोन eSIM और नियमित सिम कार्ड दोनों के साथ काम करता है तो यह कोई समस्या नहीं है, लेकिन यह iPhone 14 US मॉडल जैसे उपकरणों के साथ है, जो केवल eSIM के साथ काम करता है।

टेल्को अधिक शक्तिशाली हैं:

- eSIM के साथ, सिम कार्ड खरीदने के लिए टेलीकॉम ऑपरेटर के स्टोर की पहली यात्रा से बचा जा सकता है, लेकिन फोन स्विच करने के लिए अभी भी ऑपरेटर की मदद की आवश्यकता होती है।
- ऑपरेटर भविष्य में eSIM सब्सक्रिप्शन या फोन स्वैपिंग के लिए अतिरिक्त शुल्क लगा सकते हैं।

- *स्रोत→हिन्दू*

GURU DEEKSHAA IAS

संपादकीय विश्लेषण

1. ईडब्ल्यूएस आरक्षण:

ईडब्ल्यूएस कोटा: ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:

- 10% आरक्षण 103 वें संविधान संशोधन द्वारा पेश किया गया था, जो जनवरी 2019 में प्रभावी हुआ।
- इसने अनुच्छेद 15 में खंड (6) जोड़ा ताकि सरकार को उन वर्गों के लोगों को छोड़कर, जिनके पास पहले से ही आरक्षण है, ईडब्ल्यूएस के लिए विशेष प्रावधान बनाने की शक्ति प्रदान की जा सके।
- शैक्षणिक संस्थानों में, सार्वजनिक और निजी दोनों, चाहे वह सहायता प्राप्त हो या गैर-सहायता प्राप्त, अल्पसंख्यक संस्थानों द्वारा चलाए जा रहे लोगों के अपवाद के साथ अधिकतम 10% आरक्षण की अनुमति है।
- इसके अतिरिक्त, इसने रोजगार में आरक्षण की सुविधा के लिए अनुच्छेद 16 में खंड (6) जोड़ा।
- अतिरिक्त शर्तें यह स्पष्ट करती हैं कि ईडब्ल्यूएस रिजर्व को मौजूदा आरक्षण में जोड़ा गया है।

ईडब्ल्यूएस कोटा की शुरुआत:

- ईडब्ल्यूएस आरक्षण मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) एसआर सिंहो के निर्देशन में एक आयोग द्वारा दिए गए सुझावों के परिणामस्वरूप दिया गया था।
- आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आयोग की स्थापना तत्कालीन यूपीए प्रशासन द्वारा 2005 में की गई थी, और इसने जुलाई 2010 में अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की।
- इसके आधार पर, कैबिनेट ने जनवरी 2019 में 103वें संशोधन को लागू करने का फैसला किया, जिसमें ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण शामिल है।
- नई समिति का गठन किस उद्देश्य से हुआ?
- संविधान की अनुच्छेद 15 की व्याख्या की आवश्यकताओं के आलोक में, समिति ने आर्थिक रूप से कमजोर क्षेत्रों के निर्धारण के लिए मानदंडों का आकलन करने की मांग की।
- सुप्रीम कोर्ट की घोषणा के बाद कि ईडब्ल्यूएस निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली आय मानदंड "मनमाना" था, इसे लागू किया गया था।

कोटा का क्या मतलब है:

- आर्थिक रूप से वंचित समूहों को सशक्त बनाना: 10% कोटा प्रगतिशील है और शैक्षिक और आय असमानता के साथ भारत के मुद्दों को संबोधित कर सकता है, क्योंकि इसके नागरिकों के आर्थिक रूप से वंचित समूहों को उनकी वित्तीय अक्षमता के कारण उच्च शिक्षा संस्थानों और सरकारी रोजगार से रोक दिया गया है।
- आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की संवैधानिक मान्यता: आर्थिक रूप से वंचित वर्गों के अलावा, कई और व्यक्ति और संगठन हैं जो भूख और गरीबी का अनुभव करते हैं।
- एक संवैधानिक संशोधन के माध्यम से, परिकल्पित आरक्षण निम्न जाति के गरीबों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करेगा।
- जाति-आधारित भेदभाव में कमी: चूंकि जाति ऐतिहासिक रूप से आरक्षण से जुड़ी हुई है और उच्च जाति आमतौर पर आरक्षण के माध्यम से प्रवेश करने वालों को नीची नज़र से देखती है, इससे धीरे-धीरे आरक्षण से जुड़े कलंक को कम किया जा सकेगा।

- सुप्रीम कोर्ट ने राम सिंह बनाम भारत संघ (2015) में तर्क दिया कि सामाजिक मुद्दे जाति की अवधारणा से परे जा सकते हैं (उदाहरण के लिए, ट्रांसजेंडर लोगों के मामले में आर्थिक स्थिति या लिंग पहचान)।

अनुभाग का निर्धारण करते समय किन मानदंडों पर विचार किया जाता है?

- मुख्य शर्त यह है कि रुपये से अधिक वार्षिक वेतन वाले लोग। 8 लाख को बाहर रखा गया है।
- यह आवेदन से पहले वित्तीय वर्ष के लिए परिवार, आवेदकों, और उनके माता-पिता, भाई-बहनों और नाबालिग बच्चों के लिए वेतन, व्यवसाय, खेती और पेशे सहित सभी स्रोतों से आय प्रदान करता है।

इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित में से किसी भी वस्तु के स्वामी होने से व्यक्ति EWS पूल से बाहर रह सकता है:

- कृषि के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि जो कम से कम पांच एकड़ हो।
- एक घर जो 1,000 वर्ग फुट या उससे अधिक है।
- अधिसूचित नगर पालिकाओं में कोई भी आवासीय भूखंड जो 100 वर्ग गज या उससे बड़ा हो।
- कम से कम 200 वर्ग गज का घर जो कहीं और स्थित हो।

अदालत के मानकों के बारे में क्या चिंताएं हैं?

- सामान्य श्रेणी के भीतर कमी: ईडब्ल्यूएस कोटा अभी भी आग के अधीन है, क्योंकि इसके आलोचकों की राय में, यह कुल आरक्षित पर 50% की सीमा से अधिक होने के बावजूद खुली श्रेणी के आकार को कम करता है।
- आय सीमा में मनमानी: आय सीमा, जो प्रति वर्ष $ 8 लाख तय की गई है, ने अदालत को चकित कर दिया है। ओबीसी आरक्षण के लाभों से "क्रीमी लेयर" को बाहर करने का खर्च समान है।
- सामाजिक और वित्तीय अज्ञानता एक उल्लेखनीय अंतर यह है कि सामान्य समूह में, जिन पर ईडब्ल्यूएस कोटा लागू है, वे ओबीसी पदनाम के तहत आने वाले लोगों के विपरीत, सामाजिक या शैक्षिक पिछड़ेपन का अनुभव नहीं करते हैं।
- फ्लैट मानदंड महानगरीय और गैर-महानगरीय स्थानों के बीच अंतर क्यों नहीं करता है, यह एक और प्रश्न है कि क्या अपवादों की पहचान करने के लिए कोई प्रयास किया गया था।
- यह वह बिंदु है जिसे अदालत ने उठाया है: जब ओबीसी वर्ग सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ जाता है, और इसके परिणामस्वरूप, अतिरिक्त बाधाओं को दूर करना होता है।
- प्रासंगिक डेटा द्वारा समर्थित नहीं सुप्रीम कोर्ट की प्रसिद्ध राय के अनुसार कि किसी भी बहिष्करण मानकों या मानदंड को प्रासंगिक जानकारी द्वारा उचित ठहराया जाना चाहिए।
- 50% आरक्षण सीमा से अधिक है: इंदिरा साहनी मामले के अनुसार, 50% आरक्षण सीमा है। समानता-संतुलन की धारणा आरक्षण की अनुमति देती है।

ईडब्ल्यूएस कोटा की वर्तमान स्थिति क्या है?

- ईडब्ल्यूएस आरक्षण पिछले दो वर्षों से केंद्र सरकार के नियंत्रण में है।

- भर्ती परीक्षाओं के परिणामों के अनुसार, इस श्रेणी में ओबीसी की तुलना में कम कट-ऑफ अंक है, जिसने लंबे समय से जाति-आधारित आरक्षण प्राप्तकर्ताओं को नाराज कर दिया है।
- कम कट-ऑफ ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए आवेदकों की कम संख्या के कारण है, जिसके लिए राजस्व अधिकारियों से आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है।
- दूसरी ओर, जैसे-जैसे समय के साथ संख्या बढ़ती है, कट-ऑफ अंक बढ़ने का अनुमान है।

ईडब्ल्यूएस कोटा के साथ व्यावहारिक समस्याएं:

- निकट भविष्य में, ईडब्ल्यूएस कोटे की अदालती समीक्षा होगी। यह केवल न्यायपालिका का मामला नहीं है; भारतीय संसद को भी क़ानून का मूल्यांकन करना चाहिए।
- रैपिड-फायर कानून यह कानून तेजी से पारित किया गया था। इसे राष्ट्रपति ने समर्थन दिया और 48 घंटे से भी कम समय में दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया।
- अल्पसंख्यकों के साथ सुलह यह आमतौर पर स्वीकार किया जाता है कि कानून एक विशिष्ट उच्च-जाति के सामाजिक समूह को खुश करने और अल्पसंख्यक आरक्षण संबंधी चिंताओं को दूर करने के प्रयास में पारित किया गया था।
- नैतिकता सवालों के घेरे में है: जरा सोचो! लक्षित आबादी से परामर्श किए बिना और केवल कुछ घंटों के विचार के बाद एक संवैधानिक संशोधन किया गया था। यह स्पष्ट रूप से अनैतिक है और संवैधानिक उपयुक्तता के विपरीत है।
- इस संशोधन का आधार झूठा है या पर्याप्त साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं है। यह अधिक से अधिक एक बेतुका अनुमान या परिकल्पना है क्योंकि सरकार ने कोई सहायक साक्ष्य पेश नहीं किया है।
- पिछड़े वर्गों के लिए अपर्याप्त आरक्षण इस दावे को कई डेटा बिंदुओं द्वारा समर्थित किया गया है जो एससी, एसटी और ओबीसी समूहों के कम प्रतिनिधित्व को प्रदर्शित करता है। इससे पता चलता है कि "उच्च" जातियाँ अधिक प्रचलित हैं (100 माइनस आरक्षण के साथ)।
- 10% औचित्य: यह अभी भी एक चुनौती प्रस्तुत करता है। एससी और एसटी कोटा उनकी कुल आबादी पर आधारित है। हालांकि, 10% प्रतिबंध के औचित्य का उल्लेख कभी नहीं किया गया था।
- समानता की धारणा: आर्थिक ठहराव की कई अलग-अलग अभिव्यक्तियाँ हैं। इसका पिछड़ा वर्ग के खिलाफ किए गए ऐतिहासिक गलत कामों और दायित्वों से कोई लेना-देना नहीं है।

क्या भारत में आरक्षण की आवश्यकता है?

- स्थिति और अवसर की समानता प्रदान करना राज्य का कर्तव्य: आरक्षण सामाजिक अन्याय और कुछ वर्गों के उत्पीड़न का मुकाबला करने का एक तरीका है। आरक्षण, जिसे अक्सर सकारात्मक कार्रवाई के रूप में जाना जाता है, उत्पीड़ित वर्गों के उत्थान में मदद करता है।
- आरक्षण समाज में सुधार के लिए केवल एक ही तरीका है: अनुदान, कोचिंग, छात्रवृत्ति, और अन्य कल्याणकारी कार्यक्रमों की पेशकश कुछ और रणनीतियां हैं।
- अभियान वित्त राजनीति भारतीय संविधान के अनुसार, केवल सामाजिक और शैक्षिक रूप से वंचित वर्ग ही

आरक्षण के लिए योग्य थे। जाति-आधारित आरक्षण ने भारत में वर्ग-आधारित आरक्षण की जगह ले ली।

- अनिवार्य आयोग की रिपोर्ट: प्रारंभ में, केवल एससी/एसटी समूहों को ही आरक्षण का लाभ मिलना था, और यह केवल 10 साल की अवधि (1951-1961) के लिए था। लेकिन तब से यह लंबा हो गया है।
- 1990 में मंडल आयोग की रिपोर्ट के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप, अन्य पिछड़े समुदायों (ओबीसी) को शामिल करने के लिए आरक्षण की सीमाओं को बढ़ा दिया गया था।
- आखिरकार, कुछ ही समूहों (या परिवारों) ने आरक्षण से लाभ उठाना शुरू कर दिया, इस प्रक्रिया में वास्तव में योग्य लोगों को अलग कर दिया। आजादी के 70 साल बाद भी आज भी आरक्षण की जबरदस्त चाहत है।
- चूंकि पहले से मौजूद जाति-स्थितियों में कोटा के लिए आर्थिक मानदंड जोड़े गए हैं, इसलिए चीजें और कठिन हो गई हैं।

आगे बढ़ते हुए:

- योग्यता का संरक्षण यह संभव है कि हमारे देश के आर्थिक पिछड़ेपन का चौंकाने वाला स्तर हमें उत्कृष्टता का पीछा करने से रोक रहा हो।
- तर्कसंगत मानक विशिष्ट सामाजिक समूहों की आर्थिक भेद्यता को परिभाषित करने और मापने के लिए आर्थिक न्याय की अवधारणा को आकार देने के लिए सामूहिक ज्ञान की आवश्यकता है।
- न्यायिक मार्गदर्शन न्यायिक व्याख्या के आधार पर, ईडब्ल्यूएस कोटा मानदंड निर्णय लेने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
- अपेक्षित दर्शक। यह निर्धारित करने के लिए कि इस आरक्षण प्रणाली का उपयोग कौन करेगा, केंद्र को अधिक तार्किक मानदंडों को नियोजित करना होगा। इस संबंध में जाति जनगणना से प्राप्त जानकारी उपयोगी हो सकती है।
- आय मूल्यांकन प्रति व्यक्ति आय, सकल घरेलू उत्पाद, और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच क्रय शक्ति में अंतर जैसे विचारों को पूरे देश के लिए एकल आय सीमा निर्धारित करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए।

निष्कर्ष:

- आरक्षण, एक संवैधानिक खंड, का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सामाजिक रूप से वंचित समूहों के व्यक्ति अन्य सभी नागरिकों के साथ राष्ट्र निर्माण की पहल में भाग लें।
- ऊपर उल्लिखित अस्पष्टताएं दर्शाती हैं कि कैसे ईडब्ल्यूएस कोटा संवैधानिक आरक्षण प्रणाली को कमजोर करता है।

2. जी 20:

के बारे में:

- 19 देशों, यूरोपीय संघ और विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रतिनिधियों का एक अनौपचारिक गठबंधन G20 बनाता है।
- G20 सदस्यता दुनिया की सबसे बड़ी विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करती है, जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 80% से अधिक, विश्वव्यापी व्यापार का 75% और वैश्विक आबादी का 60% हिस्सा है।

G20 का गठन कैसे हुआ?

- 1997-1999 के एशियाई वित्तीय संकट पर चर्चा करने के लिए विकसित और विकासशील दोनों देशों को आमंत्रित करने वाले G7 के परिणामस्वरूप, इस मंत्रिस्तरीय स्तर की सभा की स्थापना की गई थी। 1999 में, केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों और वित्त मंत्रियों की पहली बैठक हुई।
- 2008 के वित्तीय संकट के दौरान, पूरी दुनिया में नए सिरे से राजनीतिक आम सहमति बनाने की आवश्यकता को स्वीकार किया गया था। यह तय किया गया कि आगे चलकर जी20 के नेता साल में एक बार मिलेंगे।
- इन शिखर सम्मेलनों की तैयारी में सहायता के लिए, G20 केंद्रीय बैंक के गवर्नर और वित्त मंत्री अलग-अलग, दो बार वार्षिक बैठकें करते रहते हैं। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी उसी समय मिलते हैं जैसे वे मिलते हैं।

G20 की प्रक्रिया क्या है?

G20 के काम को दो ट्रैक में बांटा गया है:

- वित्त ट्रैक में G20 केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों और उनके नामितों के साथ सभी चर्चाएं शामिल हैं। वे पूरे वर्ष नियमित रूप से मिलते हैं और वित्तीय नियमों, धन और वित्त आदि सहित विषयों पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
- शेरपा ट्रैक में राजनीतिक भागीदारी, भ्रष्टाचार की रोकथाम, विकास, ऊर्जा आदि सहित व्यापक मुद्दों को शामिल किया गया है।
- एक शेरपा, जो राज्य के प्रमुख की ओर से योजना बनाने, निर्देशित करने, लागू करने आदि के लिए काम करता है, प्रत्येक G20 राष्ट्र को सौंपा जाता है। श्री शक्तिकांत दास नाम के एक भारतीय ने 2018 में अर्जेंटीना में G20 शेरपा के रूप में काम किया।

G20 में कौन शामिल है?

- अन्य G20 सदस्य सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, इटली, जापान, कोरिया, मैक्सिको, रूस, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय हैं। संघ।
- एक निरंतर गैर-सदस्य आमंत्रित के रूप में, स्पेन नेता शिखर सम्मेलन में भाग लेता है।

G20 की संरचना और उद्देश्य क्या हैं?

- समय के साथ, एक प्रणाली जो वार्षिक आधार पर G20 प्रेसीडेंसी को वैकल्पिक करती है, क्षेत्रीय संतुलन को बढ़ावा देती है।

- राष्ट्रपति चुनने के उद्देश्य से, 19 राष्ट्रों को 5 समूहों में विभाजित किया गया है, प्रत्येक समूह में अधिकतम 4 राष्ट्र हैं। राष्ट्रपति प्रत्येक गुट के बीच घूमता है। हर साल, G20 संगठन का नेतृत्व करने के लिए एक अलग समूह से एक देश का चुनाव करता है।
- भारत समूह 2 में तुर्की, दक्षिण अफ्रीका और रूस के साथ है।
- G20 का कोई निर्धारित सचिवालय या मुख्यालय नहीं है। इसके बजाय, वैश्विक अर्थव्यवस्था में बदलाव के जवाब में और अन्य सदस्यों के साथ बात करने के बाद G20 एजेंडा को एक साथ रखना G20 अध्यक्ष का काम है।
- ट्रोइका: हर साल, एक नया देश राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालता है, और यह निवर्तमान और आने वाले प्रशासन दोनों के साथ काम करता है। ट्रोइका इस प्रक्रिया का नाम है। यह समूह के एजेंडे की निरंतरता और स्थिरता सुनिश्चित करता है।

G20 के लाभ और सफलताएँ क्या हैं?

- G20 एक छोटा समूह (20 सदस्य) है जो तेजी से आगे बढ़ सकता है और बदलती परिस्थितियों के अनुकूल हो सकता है।
- आमंत्रित देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, और नागरिक समाज संगठनों को सालाना सगाई समूहों के माध्यम से दुनिया की समस्याओं का आकलन करते समय और उनसे निपटने के तरीके पर समझौता स्थापित करते समय एक व्यापक और अधिक व्यापक दृष्टिकोण को सक्षम बनाता है।
- सहयोग: जी-20 ने अंतरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने और वैश्विक स्तर पर वित्तीय विनियमन के ढांचे को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- ऐसे समय में जब निजी क्षेत्र के वित्त पोषण के स्रोत सिकुड़ रहे थे, बहुपक्षीय विकास बैंकों को अपने ऋण में 235 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि करने में सहायता मिली।
- 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान आपातकालीन नकदी का त्वरित आवंटन G20 की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक था।
- यह राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों की निगरानी में सुधार करके अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को बेहतर बनाने में भी मदद करता है। उदाहरण के लिए, कर पारदर्शिता मानकों और बेस इरोशन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग (बीईपीएस) कार्यक्रम को अपनाना, दोनों का नेतृत्व G20 और OECD द्वारा किया जाता है।
- विश्व व्यापार संगठन ने भविष्यवाणी की कि व्यापार सुविधा समझौता वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के 5.4 और 8.7% के बीच योगदान कर सकता है यदि इसे 2030 तक पूरी तरह से लागू किया गया था, इसलिए इसे अपनाने के लिए G20 आवश्यक था।
- बेहतर संचार: G20 दुनिया के शीर्ष औद्योगिक और विकासशील देशों को एक साथ लाता है ताकि समझौते को बढ़ावा दिया जा सके और चर्चा के माध्यम से निर्णय लिया जा सके।
- नवंबर 2021 में जी20 सम्मेलन में, नेताओं ने फैसला किया कि कार्बन तटस्थता सदी के मध्य तक या इसके बारे में प्राप्त कर ली जाएगी।
- रोम घोषणा का अनुसमर्थन है।
- G20 जलवायु जोखिम एटलस का एक पुराना संस्करण, जो G20 देशों के लिए जलवायु परिदृश्य, सांख्यिकी, सूचना और पूर्वानुमानित जलवायु परिवर्तन प्रदान करता है, जारी किया गया था।

G20 के सामने क्या चुनौतियाँ हैं?

- कोई प्रवर्तन तंत्र नहीं है G20 के टूलसेट में सामान्य, मापने योग्य उद्देश्यों और समन्वित कार्रवाई के साथ-साथ पारदर्शी सूचना आदान-प्रदान और सर्वोत्तम प्रथाओं पर समझौते शामिल हैं। इसमें से कोई भी सर्वसम्मति के बिना पूरा नहीं किया जाता है और इसे लागू नहीं किया जाता है, सहकर्मी समीक्षा और सार्वजनिक जवाबदेही द्वारा पेश किए गए प्रोत्साहन के अपवाद के साथ।
- क्योंकि निर्णय बातचीत और समझौते के परिणाम हैं जो घोषणाओं का रूप लेते हैं, वे कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं हैं। ये दावे बाध्यकारी अनुबंध नहीं बनाते हैं। केवल 20 लोग ही इस सलाहकार या सलाहकार निकाय को बनाते हैं।
- परस्पर विरोधी हित: G20 बैठक नवंबर 2022 में होगी, और रूस और यूक्रेन के राष्ट्रपतियों को आमंत्रित किया गया है।
- यदि रूसी राष्ट्रपति को आमंत्रित किया जाता है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका पहले ही भाषण का बहिष्कार करने की धमकी दे चुका है।
- नाटो की प्रगति, चीन के रणनीतिक विकास और अब क्रीमिया यूक्रेन संघर्ष में रूस की क्षेत्रीय आक्रामकता के कारण 2022 में वैश्विक प्राथमिकताओं में बदलाव आया।
- वैश्वीकरण अब एक ट्रेंडी विचार नहीं है क्योंकि अधिक देश जी -7, जी -20, ब्रिक्स, पी -5 (यूएनएससी स्थायी सदस्य), और अन्य बहुपक्षीय संगठनों को "जी-जीरो" (एक शब्द गढ़ा) होने के पक्ष में चुनते हैं। राजनीतिक टिप्पणीकार इयान ब्रेमर द्वारा "एवरी नेशन फॉर इटसेल्फ") का अर्थ है।

भविष्य क्या ला सकता है?

- दुनिया की सभी समस्याओं का समाधान G20 द्वारा नहीं किया जा सकता है। लेकिन पिछले दस वर्षों में, G20 का वैश्विक सहयोग पर काफी प्रभाव पड़ा है।
- प्रभावी वैश्विक शासन, जी20 की तरह, आवश्यक है क्योंकि उभरते हुए राष्ट्र वैश्विक व्यवस्था को प्रभावित करने और योगदान करने के तरीकों की खोज करते हैं।
- G20 को IMF, OECD, WHO, विश्व बैंक और WTO सहित वैश्विक संगठनों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना चाहिए और उन्हें विकास की निगरानी का कर्तव्य सौंपना चाहिए।
- सभी सदस्य देशों की भलाई के लिए राष्ट्रीय हितों पर वैश्विक सहयोग को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
- यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध और रूस और पश्चिम के बीच मतभेदों जैसे मुद्दों को हल करने के लिए बातचीत और कूटनीति का उपयोग किया जाना चाहिए।
- भारत को 2023 में जी20 शिखर सम्मेलन को एक मंच के रूप में उपयोग करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए ताकि गंभीर व्यापार प्रतिबंधों और दंड, अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों और वैश्विक सहयोग और शांति को आगे बढ़ाने जैसे मुद्दों पर चर्चा की जा सके।

Guru Deekshaa IAS is happy to announce first ever kannada current affairs magazine for kannada medium aspirants of Karnataka. The three important thumb rules for any competitive exam are

Vijay Kumar G

Founder and Director

Guru Deekshaa IAS

- First-NCERT/STATE syllabus books which helps to develop your understanding on the subjects
- Second-Daily current affairs helped to build your further understanding of the events related to your examination, Apart from knowledge it build the personality of an individual which brings in confidence to face any examination.
- Third-Practice previous year question papers and mock test available in the market to train your mind as per the requirement of the examination.

Thousand miles of journey starts with single step, We at Guru Deekshaa have taken this first step towards empowering you to prepare for civil for services. Now its your turn to start preparation and achieve your dream of becoming IAS/IPS.

CALL US FOR MORE DETAILS

76 76 74 98 77

JOIN OFFICIAL TELEGRAM FOR MATERIAL AND UPDATES

@GURU_DEEKSHAAIAS

FOLLOW OUR INSTAGRAM FOR DAILY UPDATES

GURUDEEKSHAA